

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942- सितम्बर 14, 2020 <i>Bhadra 23, Monday, Saka 1942- September 14, 2020</i>	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 14, 2020

संख्या प.2(37)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 20)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1973 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 17 का संशोधन.- राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं. 11) की धारा 17 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (6) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(5-क) उप-धारा (1) से (4) तक की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसने उस पर लागू होने योग्य अधिकतम-सीमा क्षेत्रफल से अधिक कोई भूमि अर्जित कर ली है या अर्जित करता है और उक्त भूमि को, सौर या पवन शक्ति का उत्पादन करने के लिए, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 में यथापरिभाषित सौर फार्म/पार्क, सौर संयंत्र/सौर शक्ति संयंत्र या संबंधित क्रियाकलापों अथवा राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति, 2019 में यथापरिभाषित

पवन फार्म, पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं या संबंधित क्रियाकलापों के प्रयोजन के लिए, उपयोग में लेने का प्रस्ताव किया है या प्रस्ताव करता है:

परन्तु ऐसे व्यक्ति को-

- (i) ऐसी भूमि को, सौर फार्म/पार्क, सौर संयंत्र/सौर शक्ति संयंत्र या पवन फार्म, पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाएं स्थापित करने के लिए या संबंधित क्रियाकलापों के लिए, उपयोग में लेने के प्रयोजन के लिए, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 20) के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर या भूमि के अर्जन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर राज्य सरकार को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। राज्य सरकार ऐसे आवेदन को एक वर्ष के अवसान के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगी यदि आवेदक राज्य सरकार का यह समाधान करा देता है कि एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के पर्याप्त कारण थे;
- (ii) सौर फार्म/पार्क, सौर संयंत्र/सौर शक्ति संयंत्र या पवन फार्म, पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं के विकास के लिए या संबंधित क्रियाकलापों के लिए, उक्त भूमि को उपयोग में लेने की अनुज्ञा की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, ऐसे प्रयोजन के लिए उक्त भूमि का उपयोग प्रारंभ करना होगा। राज्य सरकार, पर्याप्त कारण दर्शित किये जाने पर, ऐसी कालावधि को दो वर्ष की और कालावधि तक बढ़ा सकेगी।"; और
- (ii) उप-धारा (7) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (5) या उप-धारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति उप-धारा (5) या, यथास्थिति, उप-धारा (6) के उपबंधों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (5), (5-क) या उप-धारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति उप-धारा (5), (5-क) या, यथास्थिति, उप-धारा (6) के उपबंधों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, September 14, 2020

No. F. 2(37)Vidhi/2/2020.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Krishi Joton Par Adhiktam-Seema Adhiropan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (2020 Ka Adhiniyam Sankhyank 20):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN IMPOSITION OF CEILING ON AGRICULTURAL HOLDINGS
(AMENDMENT) ACT, 2020****(Act No. 20 of 2020)**(Received the assent of the Governor on the 11th day of September, 2020)*An**Act**further to amend the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 11 of 1973.- In section 17 of the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973),-

(i) after the existing sub-section (5) and before the existing sub-section (6), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

“(5-A) Nothing in sub-sections (1) to (4) shall apply to a person who has acquired or acquires any land in excess of the ceiling area applicable to him and has proposed or proposes to use the said land for the purpose of Solar Farm/Park, Solar Plant/Solar Power Plant or related activities as defined in Rajasthan Solar Energy Policy, 2019 or Wind Farm, Wind-Solar Hybrid Projects or related activities as defined in Rajasthan Wind and Hybrid Energy Policy, 2019 for the generation of solar or wind power:

Provided that such person shall have to-

- (i) submit an application to the State Government within one year from the date of coming into force of the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Act, 2020 (Act No. 20 of 2020) or within a period of one year from the date of acquisition of land, for the purpose of using such land for setting up Solar Farm/Park, Solar Plant/Solar Power Plant, or Wind Farm, Wind-Solar Hybrid Projects or related activities. The State Government may entertain such application after expiry of one year if the applicant satisfies the State Government that there were sufficient reasons for not moving the application within the period of one year;
- (ii) commence the use of said land for development of Solar Farm/Park, Solar Plant/Solar Power Plant, or Wind Farm, Wind-Solar Hybrid Projects or related activities within a period of three years from the

date of permission to use the said land for such purpose. The State Government on sufficient cause being shown may extend the period by further period of two years.”; and

- (ii) in sub-section (7), the existing expression “in sub-section (5) or sub-section (6) contravenes the provisions of sub-section (5) or sub-section (6)”, the expression “in sub-section (5), (5-A) or sub-section (6) contravenes the provisions of sub-section (5), (5-A) or sub-section (6)” shall be substituted.

विनोद कुमार भारवानी,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।